

सं
 नंबर ६
 आरक्षण का
 डिकम की तारीख
 में जारी है।

7/1/2020

पत्रावली पेश हुई। इनप पक्ष के अनिर्भाषक उपस्थित।
 मामले में इनप पक्ष की क्लेम सुनी गई।

विहार अधिवक्ता अमीलांकरण ने क्लेम करते हुए
 बताया कि प्राथमिक न्यायालय में प्रती साक्षीवक
 ने एक शर्तना-पत्र अंतरिम धारा 2(2) के RT Act
 के पेश कर अपने कोतवाली को (नं० 1787) में दस्तावेज
 हेतु अमीलांकरण के कोटे ७२७ 1786 में से शपथ मांगा।
 अंतरिम एमि कौन्सिलर को डी कोर्ट डी. 4.4.18 को प्रॉपरा
 कॉमिशन का आदेश जारी किया कि वह क्लेम दाखिल करे।
 अमीलांकरण कोर्टो जारी किया जो एक्तरणा (Exports)
 है क्योंकि प्रॉपरा जंजम के तहत अमीलांकरण को क्लेम
 सुनना नहीं है। ए के ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया
 गया। (नं० 1786) में नजदी नजदी में पेशित क्लेम

P.T.O.
 राजपुर

7.1.2020

350
350
350

7.1.2020

परिचयी भाग पर 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया गया है। यह रास्ता ख. नं० 1784 तथा 1786 की इन्वेंट्री भाग पर दिया जाता तो ज्यादा उपयुक्त रहना इसलिए इजीलायट इन्डिया विजिनेसमन एवं न्याय सेशन नहीं है।

आधीकम इजीलायट ने यह बातों को बताया कि ख. नं० 1784 व ख. नं० 1784 ग्राम खांगटा में खातेदारों द्वारा नक्शे में दर्शाए हुए भूमि का 2 बिघा 10 किल्लांशी तथा 2 बिघा 12 किल्लांशी भूमि राज्य सरकार को समर्पित की है जो दोनो खासों की इन्वेंट्री भाग (ख. नं० 1786 की डूबी भाग) पर है जो सार्वजनिक रास्ता के रूप में प्राचीन रिपोर्ट को देख उपलब्ध है। आधीकम इजीलायट ने पार्स 2.3 के साथ इन्हें दोनो समर्पणनामों की उतियां भू नदमीलक पीपलशाह द्वारा पटवारी हलका खांगटा को इन समर्पणनामों के इन्वेंट्री भाग राजस्व रिपोर्ट में इन्कल रिपोर्ट करने के पत्र/ इन्डिया के पेश की जो शामिल बिफल भी गयी है, इन इन्डिया के साथ नक्शा क्रिपतवार (P-35 का क्रमांक 1805/1217/118) भी संलग्न है जो पत्रवली में उपलब्ध है, इन नक्शों में समर्पित भूमि को दर्शाया हुआ है। आधीकम इजीलायट ने यह भी बताया कि इन्हें समर्पित भूमि राजस्व भूमि के ख. नं० 1785 की भूमि से सीधी जुड़कर ख. नं० 1783 के खातेदारों के लिए भी रास्ते के रूप में जाने जाने हेतु इन्वेंट्री में लेने के लिए सुलभ हो रही है इसलिए रास्ते का यह उपलब्ध बेहतर विकल्प प्राचीन रिपोर्ट के लिए भी इन्डिया है।

आधीकम रिपोर्टों के भी अपनी कदम में बताया कि इजीलायट इन्डिया से जो रास्ता दिया जा रहा है वह सीधा सड़क से जुड़ता है। इजीलायट न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर ख. नं० 1786 में प्रदत्त रास्ता जो एनवी डूबी भाग पर डाल कर दर्शाए करते उपलब्ध करता है वह सही है। रास्ते की महती आवश्यकता को भी इनमें में रखा गया है। इजीलायट इन्डिया विजिनेसमन है और इनमें कोई त्रुटि नहीं होने से इजीलायट इजीलायट खासियत भोगने को है कार्रवाई की जाये।

P.T.O
राजस्थान सरकार
जयपुर

नं. 1786
 नं. 1786
 नं. 1786

1/2020

उत्तर पक्ष की क्लेम पर मन्नत किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का इन्वेलोक्म किया। जार्जिया/ रेस्पॉण्डेंट को रान्ने की आल्फेन्सिक आक्वडक्ला के अदुनेजत अजीलाधीन आदेश से रान्ना किया गया है। अजीलाधीन पक्ष का तर्क रहा है कि रान्ना दोनो खसरो की उन्नयतिख सीमा पर किया जाना इच्छित और न्यायसंगत है। चूंकि प्रकृत समर्पण - नामो और तहसीलदार पीपाइ शहर के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अजीलाधीन द्वारा प्रकट की गई मंत्रा के अदुदण दोनो जिन: 1786 व 1785 में खे भूमि समर्पण होकर इनकी उन्नयतिख मार (सीमा) पर राज्य सरकार में निहित हो चुकी है और वह राजकीय भूमि जिन: 1785 से जुड़ जाती है जो ऊंगे सदक तक भी पहुंच जाती है। रेस्पॉण्डेंट-जार्जिया के लिए रान्ना का विकल्प उपलब्ध हो चुका है इसलिए अजीलाधीन आदेश से प्रदान रान्ने की ऊंगे आक्वडक्ला नहीं रहे जाती है। इस तथ्य को रेस्पॉण्डेंट ने भी ऊंगे रिकॉर्ड इन्वेलोक्म इच्छित मानकर अंगीकार किया गया है। लिहाजा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अजीलाधीन आदेश की प्रभावत रचना का कोई अर्थोच्छेद नहीं है। चूंकि रेस्पॉण्डेंट-जार्जिया को हमारे क्लेमर विकल्प रूप में रान्ना हेतु राजकीय भूमि बिना किसी अतिकर शारी के प्राप्त हो रही है, उपलब्ध हो रही है। अजीलाधीन ने भी अपनी खोतेदारी जिन: 1786 का कुछ भाग समर्पण किया है जिसे रेस्पॉण्डेंट को रान्ने की आक्वडक्ला की पूर्ति हो जाती है। हमारे उत्तर पक्ष के कलवा ख: नं. 1782 के खोतेदारी को भी इन्वागमन की सुविध्य का लाभ मिलेगा। समग्र रूप में अजीलाधीन आदेश निरस्त किया जाने योग्य है।

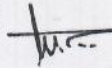
अजील अजीलाधीन आंगिक स्वीकार की जाकर अजीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पीपाइ शहर रेस्पॉण्डेंट द्वारा अतिकर रूप में चार्ज बोर्ड राशि जमा कराई जाती है, उसे पुनः लौटा दे। वह समर्पण भूमि का

P.T.O

[Signature]

राजस्व रिकॉर्ड में अमल इरादत और लहारा
द्वारा प्रपरोक्मानुवाद तरीक़ा सुनिश्चित करे।
आदेश से इजलास बुकाना गना।

पत्रावली पैसल शुमाट होकर नंबर
से कम हो। जाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।
अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मज एत इदेश
की प्रति के लॉयड जाने।


राजस्व मनीष शाधिकारी
बीकानेर